

[2011] 9 एस. सी. आर. 439

म्यूनिअल मोची

बनाम

बिहार राज्य और ए. एन. आर.

(2011 की आपराधिक अपील सं. 1429)

21 जुलाई, 2011

[पी. सतशिवम और डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायमूर्तिगण]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947: धारा 5 (1) , (ग) (घ), 5 (2) और 5 (3), परंतुक-न्यूनतम सजा एक वर्ष की-सजा कम करने के लिए न्यायालय की शक्ति निचली अदालत यू/एस. एस. द्वारा दोषसिद्धि। 120 - बी, 420, 467, 468, 471-ए आईपीसी आर/डब्ल्यू एसएस। 5 (1) (घ), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2)-उच्च न्यायालय द्वारा सजा को ढाई साल से घटाकर डेढ़ साल करने पर रोक सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर. आई. याचिका-अभिनिर्धारित: इसे ध्यान में रखते हुए एस के लिए प्रावधान। 5 (3) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ कि अभियुक्त की आयु 71 वर्ष है और वह पहले ही 6 महीने से गुजर चुका है कारावास, कि घटना की तारीख से, 29 साल है पारित हो गया और यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आरोपी था किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल, न्याय का उद्देश्य होगा पहले से ही अवधि के लिए वाक्य को संशोधित करके पूरा करें दंड संहिता, 1860-एस. एस. द्वारा पारित-तदनुसार आदेशित। 120 - बी, 420, 467, 468, 471-ए आई. पी. सी.-सजा/सजा। 14.09.1983 पर, डाय। एस. पी. मंत्रिमंडल (सतर्कता) बिहार सरकार, पटना के विभाग ने एक लिखित आदेश जारी किया कार्यालय प्रभारी, सतर्कता पुलिस स्टेशन, पटना के समक्ष शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसके तहत छह योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कनिष्ठ अभियंता / संबंधित विभाग/एजेंसी में से एजेंटों ने उक्त योजनाओं में सरकारी धन का दुरुपयोग किया और धारा 120-बी, 420, 467 के तहत दंडनीय अपराध किए गए, 440 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 468 , 471 (ए) आई. पी. सी. और एस. 5 (2) एस के साथ

पढ़ें। 5 (1) (घ) का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947। के आधार पर कहा गया शिकायत, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक सतर्कता मामला दर्ज किया गया पंजीकृत किया गया। जाँच के बाद, एक आरोप पत्र था प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल किया गया था पहली बार एक आरोपी के रूप में, 5 साल से अधिक समय के बाद एफ. आई. आर. दर्ज करना। विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई 21/2 वर्ष और रुपये का जुर्माना देना। 15,000 / - . याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को ढाई साल से घटाकर डेढ़ साल कर दिया। तत्काल अपील केवल प्रश्न तक ही सीमित थी। सजा का। आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1.1 अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र प्रतिबंध सजा में कमी के रूप में, न्यूनतम सजा है एस में निर्धारित। 5 (3) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। क्योंकि अपीलार्थी को यू/एस. एस. द्वारा भी दोषी ठहराया गया था। 5 (1) (ग) (घ) और 5 (2) सामान्य परिस्थितियों में, न्यायालय न्यूनतम 1 वर्ष की सजा देनी होगी। हालांकि, उप-ओं में जोड़ा गया परंतु। (3) अदालत को शक्ति देता है एक वर्ष से कम के कारावास की सजा देना। लिखित रूप में दर्ज किसी भी विशेष कारण के लिए। [पैरा 8] [444 सी-जी-एच]

1.2 यह विवाद में नहीं है कि घटना से संबंधित है अवधि 1982-83। अपीलार्थी के पद से सेवानिवृत्त हुए 01.10.2003 पर डिप्टी कलेक्टर, उससे पहले भी दृढ़ विश्वास। उन्हें 2004 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। यानी 21 साल की लंबी अवधि के बाद। हाईकोर्ट ने लिया फैसला अपील का निपटारा करने के लिए 6 वर्ष से अधिक। अपीलार्थी एक अनिश्चितता में मुकदमे का सामना करने की अग्रिपरीक्षा से गुजरा है इतनी लंबी अवधि के लिए दृढ़ विश्वास की प्रकृति के बारे में। के रूप में आज की तारीख में, अपीलार्थी की आयु 71 वर्ष है और उसके पास पहले से ही म्यूनिअल मोची v है। बिहार राज्य और ए. एन. आर. 441

6 महीने की जेल हुई। घटना की तारीख से, 29 साल बीत चुके हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है दिखाएँ कि अपीलार्थी किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल था मामला। इन परिस्थितियों में न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे। पहले से ही अवधि के लिए वाक्य को संशोधित करके गुजर चुका है। तदनुसार आदेश दिया। [पैरा 9] [445-ए-एफ] आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील 2011 का सं. 1429। उच्च न्यायालय के 28.07.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से सी. आर. एल. में पटना में न्यायिक

न्यायालय। अपील (एस. जे.) संख्या 600 का 2004 . अपीलार्थी की ओर से नागेंद्र राय, टी. महिपाल। उत्तरदाताओं के लिए गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

न्यायमूर्ति पी . सदाशिवम 1. स्वीकृति प्रदान की गई।
2. यह अपील आम फाइनल के खिलाफ निर्देशित है। विद्वान द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.07.2010 पटना में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश 2004 की आपराधिक अपील (एस. जे.) सं. 600 जो द्वारा दायर की गई थी आपराधिक अपील (एस. जे.) सं. के साथ इसमें अपीलार्थी। 576 , 595 , निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील की गई और सजा को ढाई साल से घटाकर डेढ़ साल।

3. संक्षिप्त तथ्य: (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की कई योजनाएं वर्षों के बीच निष्पादित कार्यक्रम (संक्षेप में "एन. आर. ई. पी".) 1982-83 जिला आरा के पीरो में तैनात अधिकारियों द्वारा कुछ निष्पादन एजेंटों/एजेंसियों की सहायता सतर्कता विभाग की जांच के दायरे में आई। पुनः पूछताछ सहित इन 442 के तहत निष्पादित योजनाओं/कार्यों का मापन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2011] 9 एस सी आर। योजनाओं से पता चला कि ब्लॉक में तैनात कुछ स्थानीय अधिकारी कुछ योजनाओं के लिए नियुक्त एजेंटों के साथ मिलीभुगत से धोखाधड़ी से वापस ले लिया और सरकार का दुरुपयोग किया उन योजनाओं के संबंध में धन और आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए गए /इस तरह के अवमूल्यन को छिपाने के लिए दस्तावेज।

(ख) 14.09.1983 पर, एक हेम राज प्रसाद, डिप्टी गवर्नर। एस. पी. मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग, बिहार सरकार, पटना ने एक कार्यालय प्रभारी, सतर्कता पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत स्टेशन, पटना, आरोप लगाते हुए कि जिला आरा के पीरो ब्लॉक में, के तहत एन. आर. ई. पी., छह योजनाएं , योजना सं। 27 / 1982-83 , 28 / 1982 निष्पादित किया गया और उन योजनाओं में प्रारंभिक जांच के बाद, यह था पता चला कि संबंधित विभाग के कनिष्ठ अभियंता/एजेंट / एजेंसी ने उक्त में सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। योजनाएं और इस तरह के व्यक्तियों ने अपराध किया है। भारतीय संविधान की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 (ए) के तहत दंड संहिता (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) और धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण की धारा 5 (1) (डी) के साथ पढ़ें अधिनियम, 1947 (इसके बाद "पी. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। जिस पर रिपोर्ट करें (संक्षेप

में "एफ. आई. आर.") और सतर्कता पी. एस. मामला दर्ज करें। उपर्युक्त धाराओं के तहत 1983 की सं. 18। अपीलार्थी के अनुसार, एफ. आई. आर. में उसका नाम नहीं था।

(ग) 14.09.1988 पर, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), पटना के न्यायालय में शुरू किया गया। इसके बाद जाँच, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें नाम था अपीलार्थी को पहली बार अभियुक्त के रूप में पेश किया गया था, एफ. आई. आर. दर्ज होने के 5 साल से अधिक समय के बाद वह धारा 120-बी, 420, 467 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र, 468 और आई. पी. सी. की धारा 477 ए और इसके साथ पठित धारा 5 (2) के तहत पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (1) (सी) (डी)। गवाहों से पूछताछ करने के बाद, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) पटना ने दिनांकित आदेश द्वारा उपरोक्त धाराओं के तहत और उसे कठोर सजा सुनाई गई ढाई साल की अवधि के लिए कारावास और भुगतान करना 15,000 / - रुपये का जुर्माना डिफॉल्ट खंड होना।

(घ) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित, अपीलार्थी ने 2004 की आपराधिक अपील सं. 600 दायर की पटना में उच्च न्यायालय। विद्वान एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, दिनांक 28.07.2010 के विवादित निर्णय द्वारा, पारित दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया गया विचारण न्यायालय द्वारा लेकिन सजा को ढाई से कम कर दिया गया डेढ़ साल तक।

(ङ) उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

4. श्री नागेंद्र राय को सुना, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थी और श्री गोपाल सिंह, विद्वान वकील उत्तरदाताओं।

5. 11.04.2001 पर नोटिस का आदेश देते हुए, यह न्यायालय स्वयं को केवल वाक्य के प्रश्न तक ही सीमित रखा। उसी को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों को पार करने या चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने विश्वास के लिए। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि अपीलार्थी था आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी और आई. पी. सी. की धारा 5 (1) (सी) (डी) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), पटना द्वारा पी. सी. अधिनियम। द हाई न्यायालय द्वारा दायर अपील पर अकेले सजा को संशोधित किया गया अपीलार्थी पर अधिरोपित मूल सजा को कम करके उसे आई. पी. सी. की धारा 409 और 120 बी के

तहत ढाई साल के लिए आर. आई. से गुजरना होगा और डेढ़ साल के लिए आर. आई. की अवधि होगी। इसी तरह, ढाई साल के लिए आर. आई. की सजा होगी। आई. पी. सी. की धारा 467, 468, 471 और 477 ए के तहत लगाया गया और पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) और धारा 5 (1) (सी) (डी) को डेढ़ साल के लिए आर. आई. की अवधि तक कम कर दिया गया।

6. अब, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अपीलार्थी ने इसकी मात्रा में और कमी करने का मामला बनाया है। सजा?

7. श्री नागेंद्र राय, विद्वान वरिष्ठ वकील, इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कि वर्तमान अपीलार्थी नहीं था एफ. आई. आर. में उनका नाम था। लगभग 25 साल बाद दोषी ठहराया गया घटना की तारीख से और आज की तारीख तक वह 444 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में से 71 वर्ष के हैं। [2011] 9 एस सी आर। आयु ने प्रस्तुत किया कि चूंकि वह पहले ही 6 महीने से गुजर चुका था कारावास, गुजरने की अवधि उचित होगी सजा और उस हद तक कम करने के लिए प्रार्थना की। दूसरी तरफ श्री गोपाल सिंह ने कहा कि यह उपयुक्त मामला नहीं है। सजा में कमी। किसी भी मामले में, उनके अनुसार, दृष्टि में उप-धारा 3 के अनुसार कारावास 1 से कम नहीं होगा। वर्ष, इसलिए यह कमी के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है, यहां तक कि वाक्य।

8. अपीलार्थी के विरुद्ध कटौती के रूप में एकमात्र प्रतिबंध दंडादेश धारा में निर्धारित न्यूनतम दण्डादेश है। 5 (3) अधिनियम से। इसके साथ संलग्न प्रासंगिक परंतुक इस प्रकार है - निम्नानुसार: " 5. आपराधिक दुराचार।

(1) XXX

(2) XXX

(3) जो भी आदतन करता है

(i) धारा 162 या धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), या

((ii) भारतीय संविधान की धारा 165 ए के तहत दंडनीय अपराध।

दंड संहिता, के लिए कारावास से दंडनीय होगा

अवधि जो एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो हो सकती है

इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है:

बशर्ते कि न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किसी विशेष कारण के लिए कारावास की सजा दे सकता है। एक वर्ष से कम।

(4) XXX "

चूंकि, उन्हें धारा 5 (1) (सी) (डी) के तहत भी दोषी ठहराया गया था। और धारा 5 (2) सामान्य परिस्थितियों में, न्यायालय को न्यूनतम 1 वर्ष की सजा अधिरोपित करें। हालांकि, परंतु उप-धारा 3 से जुड़ी धारा अदालत को लागू करने की शक्ति देती है। किसी विशेष कार्य के लिए 1 वर्ष से कम के कारावास की सजा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया गया है।

9. यह विवाद में नहीं है कि घटना अवधि से संबंधित है 1982-83 . यहाँ तक कि 01.10.2003 पर भी वे इस पद से सेवानिवृत्त हुए डिप्टी कलेक्टर, नालंदा और मुकदमे द्वारा दोषी ठहराए गए न्यायालय, जैसा कि केवल 2004 में कहा गया था, अर्थात् 21 की लंबी अवधि के बाद।

वर्षों से। जैसा कि श्री नागेंद्र राय ने ठीक ही कहा है, उन्होंने कहा था कि अनिश्चितता का अनुमान लगाते हुए मुकदमे का सामना करने की अग्रिपरीक्षा से गुजरे इतनी लंबी अवधि के लिए दृढ़ विश्वास की प्रकृति के बारे में। यह सच है। कि अपीलार्थी का नाम एफ. आई. आर. में नहीं था। लेकिन इसके बाद 5 साल की अवधि, जब अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र दायर किया, उसे तीसरे आरोपी के रूप में दिखाया गया था। जैसा कि सही कहा गया है, श्री. अपीलार्थी राय को दोषी ठहराए जाने की धमकी दी गई थी और इन सभी 21 वर्षों के लिए सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपील का निपटारा करने में 6 साल से अधिक का समय लगा। आज की तारीख में, अपीलार्थी की आयु 71 वर्ष है और वह पहले ही 6 वर्ष से गुजर चुका है। महीनों की कैद। अगर हम घटना की तारीख पर विचार करें, तो अब 29 साल बीत चुके हैं। दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अपीलार्थी अन्य आपराधिक मामलों में शामिल था। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजना, तथ्य यह है कि घटना वर्ष 1982-83 से संबंधित है, परीक्षण के लिए चला गया 21 वर्ष और 2004 में दोषसिद्धि में समाप्त हुआ, अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया दोषसिद्धि से पहले भी सेवा से और उसकी अपील रखी गई थी उनकी वर्तमान आयु, अर्थात् 71 वर्ष और 6 महीने से गुजरने पर ध्यान देते हुए, लगभग 6 वर्षों से उच्च न्यायालय में

लंबित है। कारावास, हम महसूस करते हैं कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा को संशोधित करना।

10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, पुष्टि करते हुए अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और हाथ में मामले में विशेष परिस्थितियों के लिए, सजा केवल इस सीमा तक संशोधित किया गया है, अर्थात् कारावास की अवधि, अर्थात् मूल सजा के रूप में 6 महीने जेल में बिताए गए। इस हद तक, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश संशोधित किया जाता है। अपील की अनुमति आंशिक रूप से उपरोक्त उल्लिखित सीमा तक दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात।

आर. पी.